Research Vidyapith International Multidisciplinary Journal

(International Open Access, Peer-reviewed & Refereed Journal)

(Multidisciplinary, Monthly, Multilanguage)

* Vol-3* *Issue-5* *May 2026*

www.researchvidyapith.com ISSN (Online): 3048-7331

चुनावी सुधार और प्रतिनिधित्वः भारतीय संसदीय राजनीति में परिसीमन–महिला आरक्षण संबंध का परीक्षण

अविशा रवि

एम.ए, यूजीसी नेट, राजनीति विज्ञान, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, दिल्ली

Article Info: *(Received- 22/03/2026, Accept- 14/04/2026, Published- 10/05/2026)*

DOI- 10.70650/rvimj.2026v3i50020

सार–

संविधान (एक सौ छठा संशोधन) अधिनियम, 2023, जिसे लोकप्रिय रूप से नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में जाना जाता है, का पारित होना विधायी लैंगिक समानता की दिशा में भारत की लंबी और विवादित यात्रा में एक प्रतीकात्मक रूप से महत्वपूर्ण, हालांकि प्रक्रियात्मक रूप से स्थगित, मील का पत्थर साबित हुआ। लोक सभा और राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के लिए एक–तिहाई सीटें आरक्षित करके, इस अधिनियम ने एक ऐसे विवाद को सुलझाता हुआ प्रतीत कराया जो लगभग तीन दशकों से संसद में रुका हुआ था। फिर भी अधिनियम का कार्यान्वयन इसके प्रारंभ होने के बाद आयोजित पहली जनगणना के बाद एक नए परिसीमन अभ्यास के पूरा होने पर शर्तबद्ध किया गया था, जिससे महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व की प्राप्ति को निर्वाचन क्षेत्र के पुनर्गठन पर संवैधानिक रोक से प्रभावी रूप से जोड़ दिया गया जो स्वयं 1976 से अनसुलझा रहा था। यह पत्र इस परिसीमन–आरक्षण संबंध के ऐतिहासिक, कानूनी और राजनीतिक आयामों का एक महत्वपूर्ण परीक्षण करता है, जो 1996 में महिला आरक्षण विधेयक की शुरुआत से लेकर संविधान (एक सौ इकतीसवां संशोधन) विधेयक, 2026 की शुरुआत तक इसके विकास को रेखांकित करता है, जो लोक सभा को 543 से बढ़ाकर 850 सीटों तक विस्तारित करने और परिसीमन को 2026 के बाद की जनगणना की आवश्यकता से अलग करने का प्रस्ताव करता है। संसदीय कार्यवाही और समकालीन नीतिगत टिप्पणियों के विश्लेषण द्वारा पूरक एक सैद्धांतिक–ऐतिहासिक पद्धति का उपयोग करते हुए, यह पत्र तर्क देता है कि इन दो सुधार प्रक्रियाओं के बीच का संबंध, प्रक्रियात्मक रूप से बचाव योग्य होते हुए भी, व्यावहारिक रूप से महिलाओं के लिए सार्थक विधायी प्रतिनिधित्व को लगभग एक दशक तक टालने का काम करता है, जबकि इसके साथ ही उच्च–प्रजनन क्षमता और कम–प्रजनन क्षमता वाले राज्यों के बीच संघीय संतुलन के संबंध में लंबे समय से चली आ रही चिंताओं को फिर से खोलता है। यह पत्र लैंगिक प्रतिनिधित्व और केंद्र–राज्य संबंधों दोनों के लिए प्रस्तावित 2026 के संशोधन के निहितार्थों के मूल्यांकन के साथ समाप्त होता है, और भविष्य के चुनावी सुधार को इस तरीके से क्रमबद्ध करने के लिए सिफारिशें प्रदान करता है जो इन प्रतिस्पर्धी प्राथमिकताओं को बेहतर ढंग से संतुलित करता है।

मुख्य शब्द– परिसीमन, महिला आरक्षण, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, भारतीय संसद, चुनावी सुधार, संघवाद, राजनीतिक प्रतिनिधित्व

1. परिचय–

भारत में चुनावी सुधार ऐतिहासिक रूप से व्यापक पुनर्रचना के बजाय क्रमिक, और अक्सर लंबी, विधायी वार्ताओं के माध्यम से आगे बढ़े हैं। निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन और महिलाओं के लिए विधायी आरक्षण के अंतर्ग्रथित इतिहास की तुलना में इस पैटर्न को स्पष्ट रूप से चित्रित करने वाले कुछ ही उदाहरण हैं। दोनों

प्रक्रियाएं प्रतिनिधि लोकतंत्र के सबसे मौलिक प्रश्न को छूती हैं– विधायिका में बैठने का अधिकार किसे मिलता है, और किस आधार पर– फिर भी दोनों, संरचनात्मक रूप से समान कारणों से, लंबी अवधि के लिए विधायी और संवैधानिक अधर में निलंबित रही हैं।

परिसीमन, जनसांख्यिकीय बदलाव को प्रतिबिंबित करने के लिए निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं का आवधिक पुनर्निर्धारण और सीटों का पुनर्गठन, 1976 के बयालीसवें संवैधानिक संशोधन के बाद से भारत में स्थगित रहा है, जिसके बाद 2002 के चौरासीवें संशोधन द्वारा इस रोक को 2026 के बाद आयोजित पहली जनगणना तक बढ़ा दिया गया था। इस रोक का घोषित औचित्य उन राज्यों को दंडित करने से बचना था जिन्होंने उच्च प्रजनन दर वाले राज्यों की तुलना में अपने संसदीय प्रतिनिधित्व को कम करके जनसंख्या नियंत्रण उपायों को सफलतापूर्वक लागू किया था। जनसंख्या नीति के रूप में इसकी खूबियां जो भी हों, इस रोक का प्रभाव 1976 के बाद से निर्वाचन क्षेत्र के नक्शे को काफी हद तक अपरिवर्तित बनाए रखने के रूप में पड़ा है, भले ही भारतीय राज्यों की जनसंख्या अगले पांच दशकों में अत्यधिक भिन्न दरों से बढ़ी हो।

लोक सभा और राज्य सभाओं में महिलाओं का आरक्षण भी लगभग समान रूप से लंबे प्रक्षेपपथ का पालन कर चुका है। पहली बार 1996 में एक विधेयक के रूप में पेश किया गया, महिलाओं के लिए एक–तिहाई विधायी सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव लगातार संसदों में विभिन्न रूपों में फिर से पेश किया गया, 2010 में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के तहत राज्य सभा में पारित हुआ, लेकिन कुछ क्षेत्रीय दलों के निरंतर विरोध के बीच लोक सभा में पारित होने में बार–बार विफल रहा। यह केवल सितंबर 2023 में, नवनिर्मित संसद भवन में आयोजित एक विशेष सत्र के दौरान था, कि कानून– जिसका नाम बदलकर नारी शक्ति वंदन अधिनियम कर दिया गया और संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम के रूप में अधिनियमित किया गया– अंततः पारित हुआ, जिसे दोनों सदनों में भारी समर्थन मिला।

हालांकि, अधिनियम का पारित होना तुरंत एक महत्वपूर्ण शर्त द्वारा योग्य हो गया थारू इसका कार्यान्वयन अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद आयोजित पहली जनगणना के आधार पर परिसीमन किए जाने पर बवदजपदहमदज बनाया गया था– एक ऐसी आवश्यकता, जिसने 2026 की जनगणना के बाद तक परिसीमन पर मौजूदा रोक को देखते हुए, महिला आरक्षण की व्यावहारिक प्राप्ति को कई वर्षों तक टालने का जोखिम पैदा किया, और संभावित रूप से एक ही आगामी आम चुनाव चक्र से परे। यह पत्र परिणामी नीतिगत तनाव की जांच करता है, और संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026 की शुरुआत के माध्यम से इसके हालिया समाधान की जांच करता है, जो महिला आरक्षण के कार्यान्वयन को गति देने के लिए परिसीमन के समय को इस बाधा से अलग करना चाहता है– जबकि साथ ही लोक सभा के एक महत्वपूर्ण विस्तार का प्रस्ताव करता है।

2. सैद्धांतिक आधार

2.1 परिसीमन

भारत में परिसीमन पर विद्वत्तापूर्ण साहित्य ऐतिहासिक रूप से इस विषय के राजनीतिक महत्व की तुलना में कम रहा है, आंशिक रूप से क्योंकि परिसीमन पर रोक ने हाल तक सार्वजनिक विमर्श में इस मुद्दे को काफी हद तक सुप्त बना दिया था। बहरहाल, फ्रीज के संवैधानिक और संघीय आयामों को संबोधित करने वाली रचनाओं का एक निकाय लगातार विकसित हुआ है। फ्रीज के मूल औचित्य का परीक्षण करने वाले विद्वानों ने आम तौर पर सहमति व्यक्त की है कि यह एक वास्तविक और बचाव योग्य चिंता को दर्शाता हैरू कि सीटों का एक शुद्ध जनसंख्या–आधारित पुनर्गठन राष्ट्रीय जनसंख्या नीति द्वारा प्रोत्साहित जनसांख्यिकीय संक्रमण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दक्षिणी और अन्य निम्न–प्रजनन क्षमता वाले राज्यों को व्यवस्थित रूप से दंडित करेगा, जबकि उन राज्यों को पुरस्कृत करेगा जो परिवार नियोजन उपायों को लागू करने में तुलनात्मक रूप से धीमे रहे थे (श्रीधरन, 2004)।

विद्वत्ता के इस निकाय ने लगातार फ्रीज की समाप्ति को– जिसे मूल रूप से अस्थायी माना गया था– संघीय तनाव के एक मंडराते स्रोत के रूप में चित्रित किया है, क्योंकि बीच के दशकों में उत्तरी और दक्षिणी राज्यों की जनसंख्या वृद्धि का प्रक्षेपपथ काफी भिन्न रहा है।

2.2 महिला आरक्षण–

महिलाओं के विधायी आरक्षण पर साहित्य काफी अधिक व्यापक है, जो इसके अधिक सार्वजनिक महत्व और

शैक्षणिक स्तर पर लैंगिक और प्रतिनिधित्व के विद्वानों के लिए भारतीय मामले की तुलनात्मक समृद्धि दोनों को दर्शाता है। राय (1999) और इसके बाद विसेंडची और सहकर्मियों ने 1992 के तिहत्तरवें और चौहत्तरवें संवैधानिक संशोधनों के बाद पंचायत (स्थानीय सरकार) स्तर पर महिलाओं के लिए आरक्षण की शुरुआत का परीक्षण करते हुए पाया कि कोटा–आधारित प्रतिनिधित्व ने नीतिगत प्राथमिकताओं पर और स्वयं आरक्षित कार्यकाल से परे महिलाओं की बाद की राजनीतिक भागीदारी पर मापने योग्य, भले ही असमान, प्रभाव पैदा किए। इस साहित्य को अक्सर राष्ट्रीय स्तर के आरक्षण के समर्थकों द्वारा साक्ष्य के रूप में उद्धृत किया गया है कि कोटा–आधारित हस्तक्षेप केवल प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व के बजाय राजनीतिक संस्कृति में स्थायी बदलाव ला सकते हैं।

साथ ही, आलोचनात्मक विद्वत्ता के एक अलग निकाय ने सवाल उठाया है कि क्या राष्ट्रीय विधायी स्तर पर आरक्षण पंचायत–स्तरीय निष्कर्षों को दोहराएगा, क्योंकि लोक सभा और विधानसभा सीटों से जुड़े संसाधन, दृश्यता और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा काफी अधिक है (देशपांडे और रामचंद्रन, 2017)। इस विद्वत्ता ने आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों के घूर्णी डिजाइन की ओर भी ध्यान आकर्षित किया है– जिसके तहत एक परिसीमन चक्र में महिलाओं के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र अगले चक्र में अनारक्षित हो जाता है– एक संभावित संरचनात्मक कमजोरी के रूप में, जहां तक यह उस तरह के निरंतर, निर्वाचन क्षेत्र–विशिष्ट राजनीतिक निवेश को हतोत्साहित कर सकता है जिसे सत्ता आमतौर पर पुरस्कृत करती है।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पारित होने और उसके बाद संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026 की शुरुआत के अवसर पर हाल ही में की गई टिप्पणियों में विशेष रूप से परिसीमन–आरक्षण संबंध पर ही ध्यान केंद्रित किया गया है। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च और विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी के विश्लेषकों ने 2026 के विधेयक का विस्तृत सैद्धांतिक मूल्यांकन पेश किया है, जिसमें कहा गया है कि यह न केवल 2026 के बाद की जनगणना की आवश्यकता से आरक्षण को अलग करने का प्रस्ताव करता है, बल्कि लोक सभा को 543 से बढ़ाकर 850 सीटों तक विस्तारित करके ऐसा करने का प्रस्ताव करता है – एक ऐसा बदलाव जिसका पैमाना और औचित्य स्वयं काफी बहस के विषय बन गए हैं। यह साहित्य इस अवलोकन पर एकत्रित होता है कि 2026 का विधेयक शुद्ध पुनर्गठन के बजाय विस्तार के माध्यम से आरक्षण–परिसीमन के विरोध को दूर करने के प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है, एक ऐसा डिजाइन विकल्प जिसका उद्देश्य राज्यों के बीच सीटों के जनसंख्या–आधारित पुनर्वितरण से जुड़ी संघीय चिंताओं को कम करना है, भले ही उन्हें समाप्त न किया जाए।

3. महिला आरक्षण का लंबा रास्ताः एक ऐतिहासिक विवरण

3.1 शुरुआती विधायी प्रयास (1996–2010)

लोक सभा और राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के लिए एक–तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव पहली बार 1996 में एच. डी. देवेगौड़ा के नेतृत्व वाली संयुक्त मोर्चा सरकार के दौरान संविधान (इक्यासीवां संशोधन) विधेयक के रूप में पेश किया गया था। ग्यारहवीं लोक सभा के भंग होने के साथ विधेयक व्यपगत हो गया और 1990 के दशक के उत्तरार्ध और 2000 के दशक में कई बाद के अवसरों पर काफी हद तक समान रूप से फिर से पेश किया गया, हर बार कुछ क्षेत्रीय दलों के बीच केंद्रित विरोध के बीच पारित होने में विफल रहा। इस अवधि के दौरान विधेयक का विरोध अक्सर एक अलग, हालांकि रणनीतिक रूप से इस्तेमाल किए गए, उप–कोटा तर्क के माध्यम से व्यक्त किया गया थारू कई क्षेत्रीय दल के नेताओं ने तर्क दिया कि अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाओं के लिए एक साथ उप–कोटा के बिना महिलाओं के लिए एक सामान्य आरक्षण, पहले से ही राजनीतिक रूप से हावी सामाजिक समूहों की महिलाओं को असंगत रूप से लाभान्वित करेगा।

मार्च 2010 में एक महत्वपूर्ण, यद्यपि अंततः अधूरा, मील का पत्थर हासिल किया गया, जब विधेयक ने पर्याप्त अंतर–दलीय समर्थन के साथ राज्य सभा को मंजूरी दे दी। हालांकि, इसे लोक सभा में वोट के लिए नहीं लाया गया, जहां क्षेत्रीय विरोध का वही गठबंधन बना रहा, और विधेयक बिना कानून बने एक बार फिर व्यपगत हो गया।

3.2 2023 की सफलताः नारी शक्ति वंदन अधिनियम

विधायी प्रतिरोध 2010 के राज्य सभा वोट के बाद एक दशक से अधिक समय तक बना रहा, सितंबर 2023 तक, जब सरकार ने संसद का एक विशेष पांच दिवसीय सत्र बुलाया, जो आंशिक रूप से नवनिर्मित संसद भवन

में संसदीय कार्यवाही के संक्रमण को चिह्नित करने के लिए आयोजित किया गया था। इस सत्र के दौरान, संविधान (एक सौ छठा संशोधन) विधेयक, 2023 – नारी शक्ति वंदन अधिनियम – पेश किया गया और दोनों सदनों में भारी बहुमत से पारित किया गया, जिसे लोक सभा में विरोध में 2 के मुकाबले 454 वोट मिले, और राज्य सभा में उपस्थित और मतदान करने वाले 214 सदस्यों के बीच सर्वसम्मति से समर्थन मिला। अधिनियम ने लोक सभा, राज्य विधान सभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा में महिलाओं के लिए एक–तिहाई सीटें आरक्षित कीं, जिसमें आरक्षित सीटों को प्रत्येक परिसीमन अभ्यास के बाद घुमाया जाना था।

प्रस्ताव की पहली शुरुआत के बाद से लगभग तीन दशक के अंतर को देखते हुए, अधिनियम के पारित होने को व्यापक रूप से, और सटीक रूप से, ऐतिहासिक के रूप में चित्रित किया गया था। विश्लेषकों ने बहरहाल स्वयं अधिनियम के भीतर निहित एक महत्वपूर्ण चेतावनी को चिह्नित कियारू कार्यान्वयन को अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद आयोजित पहली जनगणना के आधार पर किए जाने वाले परिसीमन पर निर्भर बनाया गया था। यह देखते हुए कि चल रही दशक की जनगणना उस समय अपने निर्धारित 2021 के संचालन से काफी आगे विलंबित हो चुकी थी, और 2026 के बाद पहली जनगणना तक परिसीमन पर मौजूदा संवैधानिक रोक को देखते हुए, इस प्रावधान का अर्थ था कि महिला आरक्षण की व्यावहारिक प्राप्ति को यथोचित रूप से 2029 या उसके बाद तक टाला जा सकता था– एक ऐसी समयरेखा जिसे अधिनियम के पारित होने के समय कई टिप्पणीकारों ने अधिकार को ष्लागू तो किया, लेकिन संचालन में नहींष छोड़ने के रूप में वर्णित किया।

4. परिसीमन रोकरू उत्पत्ति और औचित्य

4.1 1976 का फ्रीज और इसका 2002 विस्तार

परिसीमन पर रोक का संवैधानिक आधार अनुच्छेद 81 में निहित है, जो लोक सभा की संरचना को नियंत्रित करता है, और अनुच्छेद 170, जो राज्य विधान सभाओं को नियंत्रित करता है। 1976 से पहले, परिसीमन का उद्देश्य प्रत्येक दशकीय जनगणना के बाद होना था, यह सुनिश्चित करते हुए कि राज्यों के बीच सीटों का आवंटन, और राज्यों के भीतर निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं, वर्तमान जनसंख्या वितरण को प्रतिबिंबित करती रहें। आपातकाल की अवधि के दौरान अधिनियमित 1976 के बयालीसवें संवैधानिक संशोधन ने 1971 की जनगणना के स्तर पर राज्यों के बीच लोक सभा और विधानसभा सीटों के आवंटन को यह चिंता बताते हुए रोक दिया कि परिवार नियोजन उपायों को लागू करने में अधिक सफल राज्यों को अन्यथा उच्च जनसंख्या वृद्धि वाले राज्यों की तुलना में कम संसदीय प्रतिनिधित्व के माध्यम से दंडित किया जाएगा।

यह रोक, मूल रूप से वर्ष 2000 के बाद पहली जनगणना तक जारी रखने के लिए लक्षित थी, जिसे बाद में 2002 के चौरासीवें संवैधानिक संशोधन द्वारा वर्ष 2026 के बाद आयोजित पहली जनगणना तक जारी रखने के लिए बढ़ा दिया गया था– एक विशुद्ध रूप से समयबद्ध विस्तार जिसने जनसांख्यिकीय प्रतिनिधित्व और संघीय समानता के बीच अंतर्निहित तनाव को हल किए बिना पीछे धकेल दिया। उल्लेखनीय रूप से, जबकि प्रत्येक राज्य को आवंटित सीटों की कुल संख्या को फ्रीज कर दिया गया था, 2002 के संशोधन ने राज्यों के बीच कुल सीट आवंटन को बदले बिना 2001 की जनगणना के आंकड़ों का उपयोग करके प्रत्येक राज्य के भीतर निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं के पुनर्निर्धारण की अनुमति दी – 2008 में किया गया एक आंशिक परिसीमन अभ्यास।

4.2 संघीय चिंताएं और मंडराती 2026 की समय–सीमा

जैसे–जैसे 2026 की समय–सीमा नज़दीक आई, फ्रीज का अंतर्निहित तनाव सार्वजनिक विमर्श में नए सिरे से तीव्रता के साथ फिर से उभरा। दक्षिणी राज्य– जिनमें से कई ने पहले और अधिक पर्याप्त जनसांख्यिकीय संक्रमण हासिल किया था, जिसके परिणामस्वरूप कई उत्तरी राज्यों की तुलना में पिछले पांच दशकों में तुलनात्मक रूप से धीमी जनसंख्या वृद्धि हुई थी– ने चिंता व्यक्त की कि फ्रीज की समाप्ति के बाद सीटों का एक शुद्ध जनसंख्या–आधारित पुनर्गठन मानव विकास और जनसंख्या स्थिरीकरण पर उनके मजबूत रिकॉर्ड के बावजूद, संसदीय प्रतिनिधित्व में उनके हिस्से को काफी कम कर देगा। इस चिंता को 2023–2025 के दौरान राज्य–स्तरीय प्रस्तावों और अंतरराज्यीय परामर्शों की एक श्रृंखला में अभिव्यक्ति मिली, जिसमें कई दक्षिणी मुख्यमंत्रियों ने सार्वजनिक रूप से परिसीमन अभ्यास के खिलाफ चेतावनी दी जो प्रभाव में तुलनात्मक रूप से कमजोर जनसांख्यिकीय और विकासात्मक संकेतकों वाले राज्यों की ओर राजनीतिक शक्ति को स्थानांतरित कर देता।

5. संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026, प्रावधान और निहितार्थ

5.1 मुख्य प्रावधान

संविधान (एक सौ इकतीसवां संशोधन) विधेयक, 2026, 16 अप्रैल 2026 को केंद्रीय कानून मंत्री द्वारा लोक सभा में पेश किया गया था, और 16 और 18 अप्रैल 2026 के बीच आयोजित एक विशेष संसदीय सत्र में इस पर बहस हुई थी। विधेयक भारत के चुनावी ढांचे में कई महत्वपूर्ण और आपस में जुड़े बदलावों का प्रस्ताव करता है।

पहला, यह परिसीमन को 2026 के बाद आयोजित पहली जनगणना से जोड़ने वाली मौजूदा संवैधानिक आवश्यकता को हटा देता है, जिससे केंद्र सरकार को बाद की जनगणना के पूरा होने और प्रकाशन की प्रतीक्षा किए बिना 2011 की जनगणना के आंकड़ों का उपयोग करके परिसीमन प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति मिलती है। यह प्रीक्लियरिंग सीधे 2023 के महिला आरक्षण अधिनियम द्वारा निर्मित कार्यान्वयन की बाधा को संबोधित करता है, जिससे संबंधित परिसीमन विधेयक, 2026 को 2029 के आम चुनाव के समय महिला आरक्षण को लागू करने के घोषित लक्ष्य के साथ, परिसीमन आयोग का गठन करने की दिशा में उससे काफी पहले आगे बढ़ने की अनुमति मिलती है जितना कि अन्यथा संभव होता।

दूसरा, और संघीय दृष्टिकोण से अधिक परिणामी रूप से, विधेयक लोक सभा की कुल सदस्यता को 543 से बढ़ाकर अधिकतम 850 सीटों का प्रस्ताव करता है, जिसमें 815 सीटें राज्यों के बीच और 35 केंद्र शासित प्रदेशों के बीच आवंटित की गई हैं। यह निचले सदन का सबसे महत्वपूर्ण विस्तार है जब से 1971 की जनगणना के आधार पर परिसीमन अभ्यास के बाद 543 की वर्तमान संख्या तय की गई थी।

तीसरा, साथ में परिसीमन विधेयक, 2026, एक परिसीमन आयोग के गठन का प्रावधान करता है जिसमें एक अध्यक्ष के रूप में उच्चतम न्यायालय के वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त या एक नामित चुनाव आयुक्त, और संबंधित राज्यों के राज्य चुनाव आयुक्त शामिल हैं– जो पिछले परिसीमन आयोगों की संरचना के साथ काफी हद तक सुसंगत है, जिनके आदेशों में कानून का बल होता है और वे न्यायिक चुनौती के अधीन नहीं होते हैं।

5.2 संसदीय बहस और संघवाद का प्रश्न

विधेयक की शुरुआत ने तत्काल और तीखी संसदीय बहस पैदा की, जो महिलाओं के प्रतिनिधित्व को गति देने की अनिवार्यता और दक्षिणी व अन्य निम्न–प्रजनन क्षमता वाले राज्यों की उनके सापेक्ष राजनीतिक वजन के संबंध में चिंताओं के बीच अंतर्निहित तनाव को दर्शाती है। वरिष्ठ कांग्रेस सांसद शशि थरूर सहित विपक्षी सदस्यों ने तर्क दिया कि परिसीमन को महिला आरक्षण अधिनियम से जोड़ना प्रभावी रूप से भारतीय महिलाओं की आकांक्षाओं को एक अलग और काफी अधिक संघीय रूप से विवादित प्रक्रिया के लिए बंधक बनाना था। जवाब में, केंद्रीय गृह मंत्री ने संसद को आश्वस्त करने का प्रयास किया कि विधेयक में निहित विस्तार रणनीति को विशेष रूप से दक्षिणी राज्यों के सापेक्ष प्रतिनिधित्व में किसी भी कमी को रोकने के लिए डिजाइन किया गया थारू पांच दक्षिणी राज्यों के मामले का हवाला देते हुए, सरकार ने संकेत दिया कि प्रस्तावित विस्तार के तहत पूर्ण संदर्भ में उनकी कुल लोक सभा सीटों की संख्या काफी बढ़ जाएगी, सदन में उनका आनुपातिक हिस्सा वास्तव में घटने के बजाय मामूली रूप से बढ़ जाएगा, ठीक इसलिए क्योंकि सदन के समग्र विस्तार ने राज्यों के बीच विशुद्ध रूप से जनसंख्या–आधारित पुनर्गठन के सापेक्ष प्रभाव को कम कर दिया था।

यह डिजाइन– अद्यतन जनसंख्या आंकड़ों के अनुसार मौजूदा सीटों की एक निश्चित संख्या को शुद्ध रूप से पुनर्वितरित करने के बजाय, सदन के आकार को काफी बढ़ाना – दो अन्यथा प्रतिस्पर्धी उद्देश्यों को संतुलित करने के लिए विधेयक की केंद्रीय राजनीतिक और संवैधानिक रणनीति का प्रतिनिधित्व करता हैरू प्रतिनिधित्व के लिए एक अधिक समकालीन, जनसंख्या–उत्तरदायी आधार बहाल करना, जबकि उस सीमा को सीमित करना जिस तक कोई भी एकल राज्य या क्षेत्र संसदीय वजन के पूर्ण या आनुपातिक नुकसान का अनुभव करता है। क्या यह रणनीति राजनीतिक और संवैधानिक दोनों रूप से टिकाऊ साबित होती है, यह देखा जाना बाकी है, विशेष रूप से यह देखते हुए कि विधेयक, एक संवैधानिक संशोधन के रूप में, न केवल एक विशेष संसदीय बहुमत की आवश्यकता रखता है बल्कि कम से कम आधे राज्य विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता रखता है– एक ऐसी सीमा जो स्वयं विधेयक के संघीय निहितार्थों पर निरंतर बातचीत के लिए एक संस्थागत

मंच तैयार करती है।

6. विश्लेषणात्मक चर्चाः प्रतिनिधित्व, क्रमबद्धता और राजनीतिक प्रक्रिया

इस पत्र में जांचा गया परिसीमन–आरक्षण संबंध भारतीय चुनावी सुधार की एक व्यापक और आवर्ती विशेषता का वर्णन करता है, वास्तविक रूप से लोकप्रिय और अंतर–दलीय–समर्थित सुधारों का अधिक संघीय या राजनीतिक रूप से विवादित आसपास के मुद्दों के साथ उलझने का रुझान, जिसके परिणामस्वरूप कार्यान्वयन में देरी होती है जो अंतर्निहित सुधार द्वारा स्वयं विधायी सहमति प्राप्त करने के काफी समय बाद तक बनी रहती है। 2023 में संसद के दोनों सदनों में महिला आरक्षण के लिए लगभग सर्वसम्मति से समर्थन परिसीमन के आसपास काफी अधिक बवदजमेजमक और अनसुलझी राजनीति के ठीक विपरीत है, फिर भी 2023 अधिनियम के प्रारूपण ने पूर्व को प्रभावी रूप से बाद वाले के समाधान के अधीन कर दिया।

यह क्रमबद्धता विकल्प बिना किसी बचाव योग्य संस्थागत तर्क के नहीं था। मौजूदा, दशकों पुराने निर्वाचन क्षेत्र के नक्शे के भीतर आरक्षण को लागू करने के लिए– जैसा कि कुछ लोगों ने अंतरिम उपाय के रूप में प्रस्तावित किया था– एक ऐसे ढांचे के भीतर आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की पहचान करने की आवश्यकता होती जो स्वयं जल्द ही काफी हद तक फिर से तैयार किया जाएगा, जिससे आरक्षित सीटों के एक ही आरक्षण चक्र के भीतर पुनर्गठित, विलय या समाप्त होने की संभावना बन जाती। सरकार के चुने हुए डिजाइन ने इसके बजाय संरचनात्मक संगति को प्राथमिकता दीरू यह सुनिश्चित करना कि महिला आरक्षण एक नए परिसीमन चुनावी नक्शे पर काम करेगा, ताकि ऐसी विसंगतियों से बचा जा सके। हालांकि, इस विकल्प की कीमत अधिनियम पारित होने और इसके व्यावहारिक कार्यान्वयन के बीच विश्लेषकों द्वारा अनुमानित छह से आठ साल की देरी थी– एक ऐसी देरी जो 2026 के विधेयक पेश होने से पहले और भी आगे बढ़ने का जोखिम पैदा कर रही थी, अगली दशकीय जनगणना के समय के आसपास की अतिरिक्त अनिश्चितता को देखते हुए।

तदनुसार संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026 की शुरुआत को घटना के बाद इस क्रमबद्धता समस्या को सही करने के प्रयास के रूप में समझा जा सकता है, उस जनगणना–संबंध को हटाकर जिसने अनजाने में एक प्रतीकात्मक रूप से सुलझे हुए प्रश्न– महिलाओं के विधायी प्रतिनिधित्व– को पूरी तरह से अलग और अधिक संघीय रूप से जटिल प्रक्रिया का बंधक बना दिया था। क्या यह सुधार कार्यान्वयन को सही मायने में गति देने में सफल होता है, या इसके बजाय संघीय विवादों का एक नया सेट पेश करता है जो तुलनीय देरी पैदा करने में सक्षम है, यह काफी हद तक राज्य अनुसमर्थन प्रक्रिया के परिणाम पर निर्भर करेगा जिसे 131वें संशोधन विधेयक को संवैधानिक संशोधन के रूप में गुजरना संवैधानिक रूप से आवश्यक है।

भारत की व्यापक राजनीतिक प्रक्रिया के दृष्टिकोण से, यह प्रकरण चुनावी वास्तुकला की बढ़ती प्रवृत्ति को भी चित्रित करता है– जिसे ऐतिहासिक रूप से एक बड़े पैमाने पर तकनीकी, प्रशासनिक मामले के रूप में माना जाता था– जो ठोस वैचारिक और संघीय प्रतिस्पर्धा का स्थल बन जाता है। इस अर्थ में लोक सभा विस्तार पर बहस केवल प्रतिनिधित्व की यांत्रिकी के बारे में बहस नहीं है, बल्कि भारत के अधिक और कम जनसांख्यिकीय रूप से गतिशील क्षेत्रों के सापेक्ष राजनीतिक वजन पर एक गहरी और लंबे समय से टली हुई बातचीत के लिए एक प्रतिनिधि है, एक ऐसी बातचीत जिसे 1976 के फ्रीज ने हल करने के बजाय केवल स्थगित कर दिया था।

7. सिफारिशें

पूर्ववर्ती विश्लेषण के आधार पर, यह पत्र भारत में भविष्य के चुनावी सुधार के क्रमबद्धता और डिज़ाइन के लिए निम्नलिखित सिफारिशें प्रदान करता है–

- राजनीतिक सहमति के भिन्न स्तरों वाले सुधारों को संरचनात्मक रूप से उलझाने से बचें। जहां किसी प्रस्तावित सुधार को व्यापक, लगभग सर्वसम्मत राजनीतिक समर्थन प्राप्त है– जैसा कि 2023 में महिला आरक्षण को मिला था– उसके कार्यान्वयन को, जहां संस्थागत रूप से व्यावहारिक हो, ऐसे अलग सुधारों से स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ने के लिए डिज़ाइन किया जाना चाहिए जो अधिक निरंतर राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पैदा करने की संभावना रखते हैं, ताकि बाद वाले द्वारा पूर्व वाले में देरी से बचा जा सके।
- भविष्य के परिसीमन के लिए एक पारदर्शी, सूत्र–आधारित दृष्टिकोण को संस्थागत बनाएं। प्रत्येक भावी परिसीमन चक्र में संघीय चिंता के पुनरावृत्ति को कम करने के लिए, संसद को भावी सीट पुनर्गठन के लिए एक स्पष्ट रूप से व्यक्त, सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूत्र को अपनाने पर विचार करना चाहिए – जिसमें

संभावित रूप से जनसंख्या के साथ–साथ जनसांख्यिकीय संक्रमण या विकास प्रदर्शन के भारित संकेतक शामिल हों – न कि जनसंख्या–उत्तरदायित्व और संघीय समानता के बीच संतुलन को प्रत्येक मोड़ पर नए सिरे से बातचीत करने के लिए छोड़ दिया जाए।

- घूर्णी आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों के प्रभावी कामकाज के प्रावधानों को मजबूत करें। घूर्णी आरक्षण डिज़ाइन के तहत सत्ता–आधारित राजनीतिक निवेश के संभावित कमजोर होने के संबंध में विद्वतापूर्ण चिंता को देखते हुए, आरक्षण के टिकाऊ राजनीतिक पूंजी–निर्माण क्षमता को अधिकतम करने के लिए निर्वाचन क्षेत्र की आरक्षण स्थिति के लिए विस्तारित नोटिस अवधि, या आरक्षित और अनारक्षित निर्वाचन क्षेत्रों के बीच संक्रमण करने वाली महिला विधायकों के लिए सहायता तंत्र जैसे पूरक उपायों पर विचार किया जाना चाहिए।
- सुनिश्चित करें कि उप–समूह प्रतिनिधित्व को पूरक उपायों के माध्यम से संबोधित किया जाए। यह ऐतिहासिक आपत्ति कि सामान्य महिला आरक्षण से महिलाओं के बीच पहले से ही हावी सामाजिक समूहों को असंगत रूप से लाभ हो सकता है, निरंतर ध्यान देने की मांग करती है, संभावित रूप से पूरक अंतर–पार्टी उपायों के माध्यम से– जैसे कि ओबीसी, एससी और अल्पसंख्यक महिला उम्मीदवारों के लिए पार्टी–स्तरीय उप–लक्ष्य जो संवैधानिक आरक्षण के लिए एक शर्त के बजाय उसके साथ काम करते हैं।
- जनगणना की समयानुकूलता और सार्वजनिक संचार को बढ़ाएं। जिस सीमा तक वर्तमान देरी दशकीय जनगणना के समय पर अनिश्चितता से जटिल हुई है, यह पत्र जनगणना के आंकड़ों के समय पर संचालन और प्रकाशन के लिए नए सिरे से संस्थागत और प्रशासनिक प्राथमिकता की सिफारिश करता है, केवल परिसीमन के लिए ही नहीं बल्कि डाउनस्ट्रीम सामाजिक नीति गणनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए इसकी मूलभूत भूमिका को देखते हुए।

8. निष्कर्ष–

इस पत्र में जांचा गया प्रक्षेपपथ– 1996 में महिला आरक्षण कानून की पहली शुरुआत से लेकर, 2023 में इसके अंतिम अधिनियमन के माध्यम से, 2026 में परिसीमन की अभी भी अनसुलझी राजनीति के साथ इसके उलझने तक– एक बड़े, जनसांख्यिकीय रूप से विविध संघीय लोकतंत्र में चुनावी सुधार के साथ आने वाली क्रमबद्धता चुनौतियों में एक विचारोत्तेजक मामला अध्ययन प्रस्तुत करता है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम ने कागजों पर भारतीय संसद की सबसे लंबी विधायी बहसों में से एक का समाधान हासिल किया; फिर भी इसकी व्यावहारिक प्राप्ति को दूसरे, काफी अधिक संघीय रूप से विवादित विवाद के समाधान पर निर्भर कर दिया गया, जिसकी अपनी उत्पत्ति 1976 के परिसीमन फ्रीज तक लगभग उतनी ही पीछे जाती है। संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026, महिला आरक्षण को गति देने के लिए डिज़ाइन किए गए डीकपलिंग और विस्तार के संयोजन के माध्यम से इन दो प्रक्रियाओं को अलग करने के एक जानबूझकर किए गए विधायी प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि इसके संघीय परिणामों को संभालता है। इसकी अंतिम सफलता, एक संवैधानिक संशोधन के लिए आवश्यक राज्य अनुसमर्थन प्राप्त करने में और इसके द्वारा वादा की गई त्वरित कार्यान्वयन समयरेखा प्रदान करने में, जनसांख्यिकीय रूप से उत्तरदायी प्रतिनिधित्व और टिकाऊ संघीय संतुलन के जुड़वां, और हमेशा आसानी से संगत नहीं होने वाले, अनिवार्यताओं को संतुलित करने की भारत की क्षमता का एक महत्वपूर्ण परीक्षण पेश करेगी।

Author's Declaration:

I/We, the author(s)/co-author(s), declare that the entire content, views, analysis, and conclusions of this article are solely my/our own. I/We take full responsibility, individually and collectively, for any errors, omissions, ethical misconduct, copyright violations, plagiarism, defamation, misrepresentation, or any legal consequences arising now or in the future. The publisher, editors, and reviewers shall not be held responsible or liable in any way for any legal, ethical, financial, or reputational claims related to this article. All responsibility rests solely with the author(s)/co-author(s), jointly and severally. I/We further affirm that there is no conflict of interest financial, personal, academic, or professional regarding the subject, findings, or publication of this article.

संदर्भ–

1. ऑस्टिन, जी. (1966). द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉर्नरस्टोन ऑफ ए नेशन. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
2. देशपांडे, आर., और रामचंद्रन, वी. के. (2017). डेमोक्रेटिक डेफिसिट्स, पॉलिटिक्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड रिजर्वेशन इन इंडिया. तुलिका बुक्स।
3. पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च. (2026). द परिसीमन बिल, 2026, बिल समरी. पीआरएस इंडिया।
4. पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च. (2026). द कॉन्स्टिट्यूशन (131स्ट अमेंडमेंट) बिल, 2026, बिल **समरी**. पीआरएस इंडिया।
5. राय, एस. एम. (1999). डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन एंड विमेंस एम्पावरमेंट, द कोटा डिबेट इन इंडिया. डेमोक्रेटाइजेशन, 6(3), 84–99।
6. सेन, आर. (2023). इंडियन पार्लियामेंट पासेस विमेंस रिजर्वेशन बिल. आईएसएएस ब्रीफ्स, इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशियन स्टडीज, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर।
7. श्रीधरन, ई. (2004). द ग्रोथ एंड सेक्टोरल कम्पोजिशन ऑफ इंडियाज मिडिल क्लास, इट्स इम्पैक्ट ऑन द पॉलिटिक्स ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन. इंडिया रिव्यू, 3(4), 405–428।
8. विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी. (2026). इम्प्लिकेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड लेजिस्लेटिव पैकेज ऑन परिसीमन एंड विमेंस रिजर्वेशन. विधि लीगल पॉलिसी।
9. संविधान (एक सौ छठा संशोधन) अधिनियम, 2023 (नारी शक्ति वंदन अधिनियम)।
10. संविधान (एक सौ इकतीसवां संशोधन) विधेयक, 2026।
11. परिसीमन विधेयक, 2026।

Cite this Article

"अविशा रवि", "चुनावी सुधार और प्रतिनिधित्वः भारतीय संसदीय राजनीति में परिसीमन–महिला आरक्षण संबंध का परीक्षण", Research Vidyapith International Multidisciplinary Journal, ISSN: 3048-7331 (Online), Volume:3, Issue:5, May 2026.

"Copyright © 2026 The Author(s). This work is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 (CC-BY), allowing others to use, share, modify, and distribute it with proper credit to the author."